



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2006/फाल्गुन 15, 1927

No. 89]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2006/PHALGUNA 15, 1927

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2006

सा.का.नि. 144(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक अधिकरणों के उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) लघु शीर्ष और आरम्भ — (1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक अधिकरण (उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया) नियमावली, 2006 है ।

(2) ये, शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ : इन नियमों में, जब तक इस संदर्भ में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है ।

(ख) "अधिकरण" से केन्द्र सरकार के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य सरकार के सम्बन्ध में राज्य प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है ।

### 3. चयन समिति की संरचना :-

(1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्षों और सदस्यों के चयन के प्रयोजन से एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (i) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश, अध्यक्ष ।
- (ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण;
- (iii) भारत सरकार के सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग); और
- (iv) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

(2) राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के उपाध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए - संबंधित राज्य प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्षों और सदस्यों के चयन के प्रयोजन से संबंधित राज्य सरकार की एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (i) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष;
- (ii) संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव;
- (iii) संबंधित राज्य के राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष;
- (iv) संबंधित राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ।

4. **रिक्तियाँ :** उपाध्यक्षों और सदस्यों की, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के छः महीने के ब्लॉक अर्थात् जनवरी से जून और जुलाई से दिसम्बर तक की प्रत्याशित रिक्तियाँ, चयन समिति के समक्ष रखी जाएँगी । संबंधित प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, क्रमशः न्यायिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या दर्शाएगा, जिसके पश्चात् रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तदनुसार, केन्द्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग, जैसा भी मामला हो, द्वारा शुरू की जाएगी ।

5. आवेदन-पत्र आमंत्रित करने/उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया - (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण -

- (i) चयन समिति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने और इनका चयन करने के लिए भी स्वयं प्रक्रिया निर्धारित करेगी अथवा मार्गदर्शी सिद्धांत विहित करेगी ।
- (ii) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों को लिखने के पश्चात् मंत्रालय द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची में से, चयन समिति उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए इन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी ।
- (iii) केन्द्रीय सरकार, चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (7) में दिए गए उपबंध के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्ति करने के लिए व्यक्तियों की सूची बनाएगी ।

(2) राज्य प्रशासनिक अधिकरण -

- (i) संबंधित राज्य सरकार की चयन समिति, संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित करने और चयन के लिए भी अपनी खुद की प्रक्रिया बनाएगी या मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करेगी ।
- (ii) चयन समिति, राज्य के विभिन्न नियंत्रक प्राधिकारियों को लिखने के पश्चात् राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अथवा कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची में से उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी ।
- (iii) चयन समिति की सिफारिशों पर विचार किए जाने के बाद राज्य सरकार चुने गए व्यक्तियों की एक सूची बनाएगी और उस सूची को अपनी सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगी, जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (7) में दिए गए उपबंध के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा सदस्यों की नियुक्ति करेगी ।

6. **चयन समिति की बैठकें** - (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के मामले में, चयन समिति सामान्यतः अपनी बैठकें नई दिल्ली में और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के मामले में संबंधित राज्य की राजधानी में अथवा अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठकों के स्थान के परिवर्तन के लिए कारणों को रिकॉर्ड करके, उसके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर, आयोजित करेगी ।

(2) चयन समिति की बैठक के लिए नोटिस/कार्य-सूची, जैसा भी मामला हो, अग्रिम रूप से जारी की जाएगी । बैठक की तिथि और स्थान समिति के अध्यक्ष की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

(3) बैठक के लिए न्यूनतम कोरम अध्यक्ष और कम-से-कम एक अन्य सदस्य होगा ।

7. **चयन के मानदण्ड** : प्रशासनिक अधिकरणों के सदस्यों में से उपाध्यक्ष के पद को भरने के मामले में योग्यता ही, न कि वरिष्ठता उपयुक्तता का एकमात्र मानदण्ड होगा ।

8. **भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श** : (1) चयन समिति की सिफारिशें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके मत के लिए रखी जाएँगी ।

(2) चयन समिति की सिफारिशें भारत के मुख्य न्यायाधीश के मत के साथ आदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएँगी ।

[फा. सं. ए-11013/47/2003-ए.टी.]

आर. रामानुजम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2006

G.S.R. 144(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 36 of the

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Administrative Tribunals (Procedure for appointment of Vice-Chairmen and Members) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) “Tribunals” means the Central Administrative Tribunal in relation to the Central and the State Administrative Tribunals in relation to a State.

### 3. Composition of Selection Committee.-

(1) *For selection of Vice-Chairmen and Members of Central Administrative Tribunal.*-There shall be a Selection Committee for the purpose of the selection of the Vice-Chairman and Members in the Central Administrative Tribunal consisting of the following:-

- (i) Sitting Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India, Chairman;
- (ii) Chairman, Central Administrative Tribunal;
- (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training); and
- (iv) Secretary, Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

(2) *For Selection of Vice-Chairman and Members of State Administrative Tribunals.*-There shall be a Selection Committee of the concerned State Government for the purpose of selection of the Vice Chairman and Members of the concerned State Administrative Tribunal consisting of the following:

- (i) Chief Justice of the High Court of the concerned State, Chairman;
- (ii) Chief Secretary of the concerned State Government;
- (iii) Chairman of the State Administrative Tribunal of the concerned State; and
- (iv) Chairman of the State Public Service Commission of the concerned State.

4. **Vacancies.**- The anticipated vacancies of Vice-Chairmen and Members shall be placed before the Selection Committee for a block of six months i.e., January to June and July to December of each calendar year. The Chairman of the Administrative Tribunal concerned shall indicate the number of vacancies of the Vice-Chairman and the Members to be filled from the judicial stream and the administrative stream respectively whereupon the procedure to fill up the vacancies, accordingly, shall be initiated by the Department of Personnel and Training of the Central Government or the Department concerned of the State Government, as the case may be.

5. **Procedure for inviting/processing of candidatures.**- (1) *Central Administrative Tribunal-*

(i) The Selection Committee shall devise its own procedure or lay guidelines for inviting applications as also for the selection of the Vice-Chairman and the Members of the Central Administrative Tribunal.

(ii) The Selection Committee shall recommend persons for appointment as the Vice-Chairman and Members from amongst the persons on the list of candidates prepared by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, after writing to the various cadre controlling authorities.

(iii) The Central Government shall, after taking into consideration the recommendations of the Selection Committee, and in consultation with the Chief Justice of India in accordance with the provision contained in sub-section (7) of section 6 of the said Act, make a list of persons for appointment as the Vice-Chairman and Members of the Central Administrative Tribunal.

(2) *State Administrative Tribunal-*

(i) The Selection Committee of the concerned State Government shall devise its own procedure or lay down guidelines for inviting applications as also for the selection of the Vice-Chairman and the Members of the Administrative Tribunal of the State Government concerned.

(ii) The Selection Committee shall recommend persons for appointment as the Vice-Chairman and Members from amongst the persons on the list of the candidates prepared by the Chief Secretary or Secretary, General Administration Department or Personnel Department of the State Government after writing to the various cadre controlling authorities of the State.

(iii) The State Government shall, after taking into consideration the recommendations of the Selection Committee, make a list of persons selected and send the same with its recommendations to the Central Government who will in consultation with the Chief Justice of India in accordance with the provision contained in sub-section(7) of section 6 of the said Act, appoint the Vice-Chairman or Members of the Administrative Tribunal of the State Government concerned.

6. **Meetings of the Selection Committee.-** (1) The Selection Committee shall normally hold its meetings at New Delhi in the case of the Central Administrative Tribunals and at the State capital of the State concerned in the case of the State Administrative Tribunal or at such place or places, as may be authorized by the Chairman by recording the reasons for the change of the venue of such meetings.

(2) The Notice/Agenda, as the case may be, for the meeting of the Selection Committee shall be issued in advance. The date and venue for the meeting shall be fixed with the convenience of the Chairman of the Committee.

(3) The minimum quorum for the meeting shall be the Chairman and at least, one other Member.

7. **Criteria for Selection.-** Merit in terms of suitability and not seniority shall be the sole criterion in the matter of filling up the post of the Vice-Chairman from amongst the Members of the Administrative Tribunals.

8. **Consultation with the Chief Justice of India.-** (1) The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the Chief Justice of India for his views.

(2) The recommendations of the Selection Committee, together with the views of the Chief Justice of India shall be submitted to the competent authority for orders.

[F. No. A-11013/47/2003-AT]

R. RAMANUJAM, Jt. Secy.